अंक 17, संख्या 2–3

अप्रैल–सितम्बर, 2017

जनसंदेश

भारतीय संसदीय संस्थान – जनसंख्या एवं विकास का त्रैमासिक न्यूज़लैटर

जनसंख्या संबंधी मुद्दों एवं सतत विकास भाग 3 एजेंडा 2030 के बीच अंर्तसंबंध में सांसदों की भूमिका को बढ़ाना

13–15 सितंबर 2017, नई दिल्ली, भारत

'जनसंख्या संबंधी मुद्दों तथा सतत विकास भाग 3 कार्यसूची 2030 के बीच अंर्तसंबंध में सांसदों की भूमिका को बढ़ाने' हेतु एशियाई जनसंख्या एवं विकास मंच (ए.पी.डी.ए.) द्वारा भारतीय संसदीय संस्थानः जनसंख्या एवं विकास की मेजबानी में 13–15 सितंबर, 2017, नई दिल्ली, में एक तीन–दिवसीय सम्मेलन–सह–अध्ययन दौरे का आयोजन किया गया। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या निधि, अंतर्राष्ट्रीय योजनाबद्ध पितृत्व संघ एवं जापानी ट्रस्ट फंड द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

लगभग 100 प्रतिभागियों के समूह ने इस सम्मेलन में भाग लिया। उपस्थित प्रतिभागियों का चयन क्षमता में वृद्धि हेतु उनकी आवश्यकता एवं प्राथमिक नीतिगत हस्तक्षेप के आधार पर किया गया जहां ज्ञान को साझा करना अधिक जरूरी था। अफ्रीकी देशों, भारत सहित एशियाई एवं यूरोपीय देशों के सांसदों; यूएनएफपीए तथा आईपीपीएफ कार्यालय प्रतिनिधियों; सरकारी अधिकारियों, जीका, ए.पी.डी.ए. तथा अन्य विकास भागीदारों एवं विशेषज्ञों ने सम्मेलन में भाग लिया।

श्रीमती विप्लव ठाकुर, सांसद तथा उपाध्यक्ष, भारतीय संसदीय संस्थानः जनंसख्या एवं विकास द्वारा सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रतिभागियों का स्वागत किया गया। उन्होंने कहा कि नई दिल्ली की यह बैठक जनसंख्या संबंधी मुद्दों एवं 2030 कार्यसूची के बीच अंर्तसंबंधों पर ध्यान केंद्रित करने के प्रति एक नवीनतम समर्पित श्रृंखला है, जिसमें विकसित तथा विकासशील दोनों तरह के देशों को जनसंख्या संबंधी मुद्दों एवं सतत् विकास को हासिल करने की दिशा में समान साझेदारी के रूप में काम करने पर बल दिया गया है।

इस अवसर पर माननीय यासुओ फुकुडा (जापान के भूतपूर्व प्रधानमंत्री), एशियाई जनसंख्या एवं विकास मंच के अध्यक्ष तथा जेपीएफपी के माननीय अध्यक्ष के संदेश को माननीय तेरहिको माशिको, सांसद, जापान, जेपीएफपी के उपाध्यक्ष, एशियाई जनसंख्या विकास मंच के निदेशक मंडल द्वारा पढ़ा गया। अपने संदेश में, माननीय यासुओ फुकुडा ने कहा कि जनसंख्या संबंधी मुद्दों को बलपूर्वक हासिल नही किया जाना चाहिए; इन्हें लोगों की सूचित पसंद के आधार पर हासिल किया जाना चाहिए। इस संबंध में, सांसद ही सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं, क्योंकि वे ही देश के नागरिकों के विचारों एवं इच्छाओं को सुनने की स्थिति में होते हैं। एशियाई संसदीय मंचः जनसंख्या एवं विकास की प्रगति के बाद, एशियाई जनसंख्या विकास मंच वर्तमान में अपना ध्यान एशिया से अंतर–क्षेत्रीय गतिविधियों तथा विकास पर दे रहा है। उदाहरण के लिए, यह सम्मेलन अफ्रीकी एवं एशियाई सांसदों हेतु एक अंतर–क्षेत्रीय परियोजना है तथा इसके उद्देश्य सतत् विकास को हासिल करने हेतु जनसंख्या संबंधी मुद्दों की दिशा में सांसदों की भूमिका को उन्नत बनाने संबंधी चर्चा करना एवं अंतर–क्षेत्रीय सहयोग बनाने पर आगे विचार करना है। उन्होंने इस आयोजन की मेजबानी के लिए भारतीय संसदीय संस्थानः जनसंख्या एवं विकास का आभार व्यक्त किया तथा आशा व्यक्त की कि यह सम्मेलन गहन बहस के माध्यम से भविष्य में मानवता के लिए आशा के रूप में कार्य करने हेतु एक प्रमुख कदम है, जिसके माध्यम से जनसंख्या संबंधी मुद्दों से निपटने एवं सतत् विकास लक्ष्यों को हासिल करने के प्रयासों में मदद मिलेगी।

अपने संदेश में, भारतीय प्रधानमंत्री, माननीय श्री नरेन्द्र मोदी ने एशियाई जनसंख्या विकास मंच तथा भारतीय संसदीय संस्थानः जनंसख्या एवं विकास

पृष्ठ 3 पर जारी ....

सम्मेलन के प्रतिभागी माननीय अतिथियों के साथ।

सम्पादक की कलम से

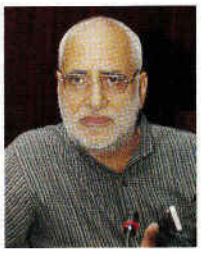

जनसंख्या संबंधी मुद्दों को संबोधित करना सतत् विकास को हासिल करने की दिशा में सबसे मूलभूत अनिवार्यताओं में से एक है। इस तथ्य का पता चला है कि अधिकांश देश, विशेष रूप से एशिया एवं अफ्रीका के देश, हाल में प्रस्तावित सहस्राब्दि विकास लक्ष्यों के तहत निर्धारित लक्ष्यों को हासिल नहीं कर पाए हैं। वास्तव में, सतत् विकास लक्ष्यों के माध्यम से भी इन मुद्दों पर मुख्यधारा संबंधी प्रतिक्रियाएं प्रदान की जानी चाहिए।

निसंदेह, भूमंडलीकरण के उभरते प्रभाव ने सभी देशों की परस्पर निर्भरता को अंत्यंत गहनता एवं विस्तार की ओर अग्रसर किया है। इसलिए, स्थायी साझेदारी को आगे बढ़ाने एवं आर्थिक रूप से व्यवहार्य समाज बनाने के लिए, विकसित तथा विकासशील, दोनों तरह के देशों को समान साझेदारों के रूप में कार्य करना होगा, जिससे वे वैश्विक साझेदारी के आधार पर अपने विविध पारस्परिक चरित्रों का उपयोग करके प्रेरणा शक्ति हासिल कर सकें।

सांसदों एवं नीति निर्माताओं के साथ पक्षसमर्थन भारत में परिवार नियोजन संबंधी प्रमुख प्रभावकों तथा निर्णय निर्माताओं के ज्ञान को बढ़ाने की दिशा में भारतीय संसदीय संस्थानः जनसंख्या एवं विकास के प्रयासों के प्रमुख स्तंभों में से एक है। यह सब संसाधनों के उच्च आवंटन एवं गर्भनिरोधक विकल्पों की विस्तारित सेवा–सुविधाओं के माध्यम से भारत में परिवार नियोजन सेवाओं की गुणवत्ता तथा पहुंच संबंधी तात्कालिकता को उजागर करने के उद्देश्य से है।

इसमें बुनियादी अंतर्निहित अवधारणा यह है कि आबादी के मुद्दों को संबोधित करने के लिए सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज प्राप्त करना जरूरी है, युवा जनसांख्यिकीय लाभांश में निवेश बढ़ाना, खाद्य सुरक्षा हासिल करना, क्षेत्रीय स्थिरता को बढ़ावा देना एवं आर्थिक रूप से एक ऐसा व्यवहार्य समाज बनाना, जहां कोई भी पिछड़ा न रहे।

जैसा कि हम जानते हैं, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है एवं यहां 1.3 बिलियन लोगों की आबादी है, जो पूरे अफ्रीकी आबादी से भी बड़ी है। विभिन्न संस्कृतियों, भाषाओं एवं जातियों की एक बड़ी संख्या के साथ एक बेहतर विविधतापूर्ण देश होने के नाते, भारत अब सबसे तेज आर्थिक विकास दर में शामिल हो गया है। देश के इस विकास कारण युवा शक्ति में निवेश करना है। भारतीय अर्थव्यवस्था का अफ्रीकी महाद्वीप, विशेष रूप से पूर्वी अफ्रीका पर काफी प्रभाव रहा है, इसका कारण इनके बीच लंबे समय तक ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं व्यावसायिक संबंधों का होना है।

इस संदर्भ में, एशिया जनसंख्या एवं विकास संघ द्वारा 'जनसंख्या मुद्दों तथा सतत् विकास भाग 3 कार्यसूची 2030 के बीच अंतर–संबंध में सांसदों की भूमिका को बढ़ाने' हेतु सितंबर 13–15, 2017 के दौरान नई दिल्ली में भारतीय संसदीय संस्थानः जनसंख्या एवं विकास की मेजबानी में एक तीन–दिवसीय सम्मेलन–सह–अध्ययन दौरे का आयोजन किया गया। सम्मेलन में अफ्रीका, भारत सहित एशिया तथा यूरोपीय देशों के सांसदों; यूएनएफपीए तथा आईपीपीएफ कार्यालय प्रतिनिधियों; सरकारी अधिकारियों, जीका, ए.पी.डी.ए. तथा अन्य विकास भागीदारों एवं विशेषज्ञों ने सम्मेलन में भाग लिया।

यह सम्मेलन समर्पित सांसदों की एक नवीनतम श्रृखला द्वारा जनसंपर्क मुद्दों एवं 2030 कार्यसूची के बीच अंतर–संबंधों पर केंद्रित था, जिसमें विकसित तथा विकासशील, दोनों देशों के बीच समान साझेदारी के उपायों के रूप में जनसंख्या संबंधी मुद्दों को संबोधित करने तथा सतत् विकास लक्ष्यों को हासिल करने हेतु कार्यबल पर जोर दिया गया।

मनमोहन शर्मा
कार्यकारी सचिव, भारतीय संसदीय संस्थानः
जनसख्या एवं विकास

श्री बूरा नरसाईया गौड, सांसद, द्वारा संसद में अभिभावकों एवं वरिष्ठ नागरिकों के रखरखाव और कल्याण पर एक विधेयक (संशोधन बिल 2016) प्रस्तुत किया गया है। श्री बूरा भारतीय संसदीय संस्थानः जनसंख्या एवं विकास के एक सक्रिय सदस्य भी हैं,

पृष्ठ 1 से आगे ....

की नई दिल्ली में सम्मेलन करने के लिए सराहना करते हुए कहा कि वैश्विक समुदाय ने कई आयामों पर विचार कर स्थायी भविष्य के लिए सतत् विकास हेतु 2030 कार्यसूची का समर्थन किया है। इस व्यापक उद्देश्य को हासिल करने हेतु स्थायी वैश्विक आबादी समान रूप से महत्वपूर्ण है। उन्होंने मानवता के लिए एक स्थायी भविष्य सुनिश्चित करने के लिए वैश्विक स्तर की नीतियां तैयार करने में अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ भागीदारी के लिए भारतीय संसदीय संस्थानः जनसंख्या एवं विकास की सराहना भी की। उन्होंने आशा व्यक्त की कि सम्मेलन के माध्यम से इस महत्वपूर्ण विषय पर इस दिशा में महत्पूर्ण बातचीत एवं विचार–विमर्श होगा।

सुश्री मैरी रोज नगुनीएफा, कैमरून की सांसद तथा जनसंख्या एवं विकास पर अफ्रीकी संसदीय मंच की अध्यक्ष द्वारा युवाओं में निवेश को बढ़ावा देने के लिए एशियाई जनसंख्या विकास मंच के साथ काम करने की तत्परता पर बल दिया, जो अफ्रीका के विकास तथा सतत् विकास के लिए 2030 कार्यसूची के संबंध में महत्वपूर्ण है।

सुश्री एना सिंह, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या निधि में भारतीय प्रतिनिधि ने कहा कि उनके देश, भारत ने स्वतंत्रता के बाद से प्रजनन दर में तेजी से गिरावट दर्ज की है एवं वर्तमान में औसत प्रजनन दर 2.2 बच्चे है, जिसे कुल प्रजनन दर 2.1 के स्तर तक नीचे लाने की चुनौती है।

अपने उद्घाटन संबोधन में, भारत सरकार के अल्पसंख्यक मामलों के केन्द्रीय मंत्री श्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि दुनिया भर में बढ़ती आबादी समान विकास के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा है एवं सतत् विकास लक्ष्य हासिल करने के लिए सभी देशों को अपनी आबादी का ध्यान रखना "अत्यंत महत्वपूर्ण" है।

उन्होंने जोर देकर कहा कि आबादी संबंधी मुद्दों पर बड़े पैमाने पर जागरूकता की आवश्यकता है, एवं बढ़ती आबादी ने संपूर्ण दुनिया के सामने सतत् विकास, रोजगार के अवसर तथा स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में समस्याएं पैदा कर दी है। श्री अविनाश राय खन्ना, पूर्व–सांसद व उपाध्यक्ष, भारतीय संसदीय संस्थानः जनसंख्या एवं विकास तथा भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी के अध्यक्ष द्वारा धन्यवाद प्रस्ताव दिया गया।

सम्मेलन के दौरान निम्नलिखित सत्र आयोजित किए गए एवं संबंधित क्षेत्र के प्रख्यात विशेषज्ञों द्वारा प्रतिभागियों को संबोधित किया गयाः

सत्र 1: सतत् विकास के लिए 2030 कार्यसूची को हासिल करने हेतु जनसंख्या मुद्दों के निहितार्थ

सत्र 2: युवाओं एवं जनसंख्या लाभांश में निवेश करना

सत्र 3: यूएचसी एवं उत्पादक स्वास्थ्यः युवाओं पर फोकस के साथ राष्ट्रीय विकास

सत्र 4: विश्व स्तरीय समझौता एवं सतत् विकास

सत्र 5: पारदर्शिता, जवाबदेही एवं सुशासन पर सांसदों की भूमिका

सत्र 6: स्थायी विकास संबंधी 2030 कार्यसूची को हासिल करने के लिए कानून की भूमिका

सम्मेलन का उद्घाटन सत्र।

समापन सत्र

समापन सत्र की अध्यक्षता मुख्य अतिथि माननीय प्रो. पी.जे. कुरियन, उपाध्यक्ष, राज्य सभा, व अध्यक्ष, भारतीय संसदीय संस्थानः जनसंख्या एवं विकास तथा उपाध्यक्ष, एशियाई संसदीय मंचः जनसंख्या एवं विकास द्वारा की गई। समापन सत्र को माननीय नागनी एफा, सांसद, कैमरून एवं अध्यक्ष, अफ्रीकी संसदीय मंचः जनसंख्या एवं विकास; माननीय डा. तोशिको अबे, सांसद तथा पूर्व मंत्री, जापान; तथा श्री वरूण कुमार आनंद, कार्यवाहक क्षेत्रीय निदेशक, अंतर्राष्ट्रीय नियोजित अभिभावक महासंघ, बैंकाक द्वारा भी संबोधित किया गया।

प्रो. पी.जे. कुरियन प्रतिभागियों को सम्बोधित करते हुए।

माननीय सुश्री नागनी एफा ने विकासशील देशों, विशेषकर अफ्रीकी देशों के बीच सहयोग बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि ऐसी कार्यशाला सहस्राब्दि विकास लक्ष्यों में सूचीबद्ध मानव जाति की सबसे अधिक दिक्कतों पर नीति निर्माताओं के ध्यानाकर्षण में सहायक होती हैं। यह सांसदों की क्षमता–निर्माण में भी बेहद मदद करतीं हैं।

सम्मेलन में प्रतिभागी भाग लेते हुए।

सम्मेलन के प्रतिभागीं माानीय उप–राष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू के साथ।

डा. तोशिको अबे प्रतिभागियों को सम्बोधित करते हुए।

डा. तोशिको अबे द्वारा सतत् विकास लक्ष्यों को सफल बनाने संबंधी कानूनी एवं बजटीय प्रावधानों के महत्व पर प्रकाश डाला गया। उन्होंने कहा कि सम्मेलन में सतत् विकास लक्ष्यों को हासिल करने के लिए सांसदों की भूमिका को सही तरीके से स्वीकार किया गया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि सांसदों का काम कुछ ऐसा होना चाहिए जो संपूर्ण सतत् विकास लक्ष्यों एवं स्थायी विकास को हासिल करने में योगदान दे सके, एवं जो मनुष्य के भविष्य में योगदान कर सकता है।

श्री वरूण कुमार आनंद द्वारा इस तरह के प्रयासों के समर्थन में आईपीपीएफ की भूमिका पर व्यापक बातचीत की गई, जिसके माध्यम से दुनिया के विभिन्न हिस्सों में सकारात्मक पक्षसमर्थन परिवर्तन लाने में योगदान मिला। उन्होंने आगे सांसदों की सतत् विकास लक्ष्यों संबधी तीन महत्वपूर्ण भूमिकाओं – कानून, बजट एवं निगरानी तथा मूल्यांकन पर बल दिया।

मुख्य अतिथि माननीय प्रो. पी.जे. कुरियन ने भारत में सम्मेलन के आयोजन के लिए एशियाई जनसंख्या एवं विकास संघ को धन्यवाद दिया। उन्होंने सम्मेलन के विभिन्न विषयों पर विशेष रूप से युवा, शिक्षा, महिला स्वास्थ्य, प्रजनन स्वास्थ्य, जनसंख्या वृद्धि, पारदर्शिता, जवाबदेही एवं सुशासन का मोटे तौर पर जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जनसंख्या वृद्धि ने पर्यावरण पर हमला किया है। मनुष्य प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, सूखा एवं भूस्खलन का बुरी तरह से सामना कर रहा हे। उन्होंने विभिन्न स्थायी मापदंडों की दृष्टि से भारत की स्थिति पर भी प्रकाश डाला। अंत में, उन्होंने इन प्रयासों के लिए कानून एवं बजटीय प्रावधानों की भूमिका पर भी जोर दिया, जिसके बिना यह उपलब्धि अधूरी रहेगी।

डा. ओसामु कुसुमोतो, महासचिव/कार्यकारी निदेशक, ए.पी.डी.ए., प्रतिभागियों को सम्बोधित करते हुए।

सम्मेलन प्रतिभागी सांसदों द्वारा नई दिल्ली घोषणपत्र पर स्वीकृति के साथ संपन्न हुआ। विभिन्न कार्य बिंदुओं में, सम्मेलन की घोषणा के माध्यम से सांसदों के लिए वैज्ञानिक ज्ञान एवं आवश्यक साक्ष्य पर आधारित ठोस नीतियां तैयार करने का आग्रह किया गया। दिल्ली घोषणापत्र में जोर देकर कहा गया कि संबंधित सरकारों द्वारा शोध संस्थानों के साथ सहयोग से इस दिशा में सभी संभावनाओं की निष्पक्ष जांच की जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त, सभी सरकारों द्वारा राष्ट्रीय, क्षेत्रीय एवं वैश्विक स्तर पर सांसदों की पर्याप्त संवेदीकरण के माध्यम से उनकी अपेक्षित भूमिका निभाने तथा आवश्यक प्रेरणा हेतु शामिल किया जाना चाहिए। इससे एशियाई जनसंख्या विकास मंच जैसे स्वतंत्र संस्थानों को संसदीय गतिविधियों के क्षेत्र में ठोस साक्ष्य–आधारित सिफारिशें करने एवं सांसदों के राष्ट्रीय संगठनों की भागीदारी सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।

क्षेत्रीय दौरा

प्रतिभागियों के लिए सरकारी अस्पताल एवं नर्सिंग कॉलेज की प्रमुख गतिविधियों को समझने के उद्देश्य से, 15 सितंबर, 2017 को लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, नई दिल्ली का क्षेत्रीय दौरा आयोजित किया गया। मेडिकल कॉलेज के निदेशक एवं नर्सिंग कॉलेज के प्रिंसिपल ने प्रतिभागियों को अपने कॉलेज की गतिविधियों के बारे में बताया।

इसके बाद प्रतिनिधिमंडल ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, नई दिल्ली की ओर प्रस्थान किया। यहां प्रतिनिधिमंडल के सामने आईआईटी, नई दिल्ली द्वारा अंधे व्यक्तियों के लिए तैयार की गई कुछ हालिया तकनीकों का प्रदर्शन किया गया। प्रतिनिधिमंडल आईआईटी, नई दिल्ली द्वारा लोगों के कल्याण हेतु प्रत्यक्ष रूप से कार्यरत रहने को देखकर अत्यधिक प्रसन्न हुआ।

अंत में, प्रतिनिधिमंडल ने संसद भवन का दौरा किया। भारत के माननीय उप–राष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू के बुलावे से पहले, प्रतिनिधिमंडल ने राज्य सभा का दौरा किया। प्रो. पी.जे. कुरियन, उपाध्यक्ष, राज्य सभा व अध्यक्ष, भारतीय संसदीय संस्थानः जनसंख्या एवं विकास ने प्रतिनिधिमंडल का स्वागत किया। इसके बाद प्रतिनिधिमंडल भारत के माननीय उपराष्ट्रपति के बुलावे पर राज्य सभा समिति कक्ष में एकत्रित हुए। परिचय के बाद, माननीय उप–राष्ट्रपति ने प्रतिनिणिमंडल को संबोधित किया। माननीय उप–राष्ट्रपति ने समावेशी सतत् विकास पर बल दिया जिसमें गरीबी उन्मूलन, जनसंख्या नियंत्रण, समावेशी विकास एवं शिक्षा प्रमुख कारक हैं। उन्होंने इस दिशा में ठोस प्रयासों पर बल दिया। उनके द्वारा दिए गए भाषण को मीडिया से अच्छा कवरेज मिला। प्रो. पी. जे. कुरियन द्वारा भी प्रतिनिधिमंडल को संबोधित किया गया।

सम्मेलन के प्रतिभागियों ने आई.आई.टी. दिल्ली (उपर) एवं लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, नई दिल्ली (नीचे) का दौरा किया।

टी.बी. रोग के कारण सामाजिक बहिष्कार उचित नहीं

अविनाश राय खन्ना, पूर्व सांसद एवं उपसभापति, भारतीय रेड क्रास सोसाईटी

विश्व में बढ़ती औद्योगिक गतिविधियों के कारण वायुमण्डल लगातार प्रदूषित होता जा रहा है। इस प्रदूषण से श्वास सम्बन्धी छोटे–बड़े अनेकों रोग पनप रहे हैं जैसे – दमा, टी.बी., भिन्न–भिन्न प्रकार के हृदय रोग, फेफड़ों का कैंसर, निमोनिया तथा खांसी, जुकाम इत्यादि। इनमें टी.बी. एक ऐसा रोग है जिसमें फेफड़ों के अन्दर कुछ विशेष प्रकार के कीटाणुओं का संक्रमण हो जाता है। वास्तव में यह लम्बी खांसी का ही एक बिगड़ा हुआ रूप है।

हाल ही में मुझे दिल्ली में वर्तमान और पूर्व सांसदों के एक कार्यदल द्वारा आयोजित विषेश बैठक में भाग लेने का अवसर प्राप्त हुआ जिसका मुख्य एजेण्डा था 'टी.बी. मुक्त भारत'। मेरे मन में विचार उठ रहा था कि क्या एक–एक रोग को लेकर ऐसे मुक्ति अभियान चलाये जा सकते हैं। परन्तु इस बैठक में कुछ घण्टे चिन्तन करने के उपरान्त जो तथ्य सामने आये उनसे यह स्पष्ट होने लगा कि वास्तव में भारत को ही नहीं सारे संसार को टी.बी. जैसे संक्रमणकारी रोग से मुक्त करवाना सभी सरकारों और राजनीतिज्ञों के साथ–साथ सभी गैर–सरकारी संगठनों के लिए भी प्राथमिकता का कार्य निर्धारित होना चाहिए।

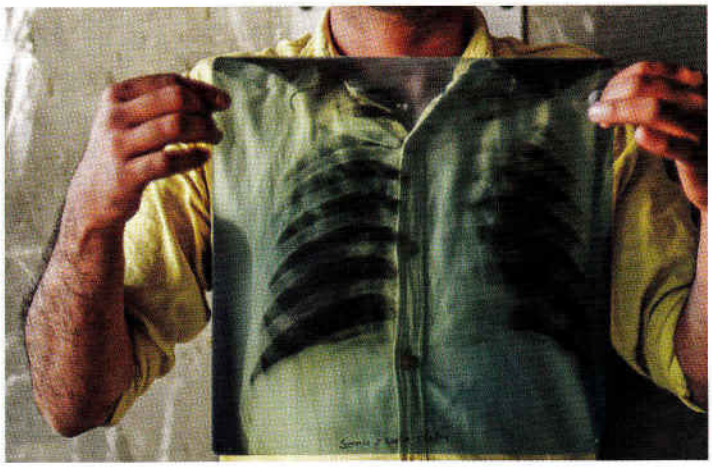

2015 के आंकड़ों के अनुसार भारत में लगभग 28 लाख टी.बी. रोगियों की संख्या थी, जिनमें से 5 लाख रोगी मृत्यु का शिकार हो गये। टी.बी. रोगियों की संख्या के मामले में भारत सारे विश्व में शिखर पर है। इतना ही नहीं सारे संसार के टी.बी. रोगियों की संख्या का 25 प्रतिशत हिस्सा भारत का है। भारत के टी.बी. रोगियों में से 10 प्रतिशत से कुछ अधिक संख्या तो अबोध बच्चों की है।

टी.बी. रोग के विरुद्ध सारे विश्व के स्तर पर एक महाअभियान छेड़ा जा चुका है। प्रारम्भ में इस अभियान की शुरुआत अफ्रीका, अमेरिका, एशिया और यूरोप के अलग–अलग गुटों से हुई थी। एशिया में इस गुट की स्थापना भारत, वियतनाम, फिलीपीन्स, इण्डोनेशिया, न्यूजीलैण्ड तथा आस्ट्रेलिया जैसे देशों की पहल पर की गई। परन्तु आज एशिया के इस टी.बी. मुक्त वर्ग में 31 देश शामिल हो चुके हैं। इसी प्रकार अफ्रीका, अमेरिका और यूरोप में भी यह अभियान जोर पकड़ता जा रहा है। भारत में इस टी.बी. मुक्ति अभियान को लेकर अब सभी राजनीतिक दलों के वर्तमान और पूर्व सांसदों ने भी अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की है। जनसंख्या और विकास के विषयों पर अभियान छेड़ने वाले इस संगठन का उपप्रधान होने के नाते मेरा यह दायित्व था कि विशेषज्ञों द्वारा एकत्रित आंकड़ों के बल पर भारत सरकार को इस रोग की गम्भीरता से अवगत करवाया जाए।

टी.बी. रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास बहुत जल्दी पहुँचता है। जिसके कारण महिलाओं और बच्चों को तो इस रोग के लगने के बाद एक यातनापूर्ण जीवन भी बिताना पड़ता है। बच्चों का स्कूल जाना बन्द हो जाता है। महिलाओं को परिवार में सामूहिक मेल–जोल से वंचित करके अलग–थलग कर दिया जाता है। कई बार तो महिलाओं को घर से निकाले जाने की घटनाएँ भी सामने आईं हैं।

टी.बी. के कारण मधुमेह (शुगर) तथा एच.आई.वी. एवं एड्स जैसे अत्यन्त गम्भीर रोगों की सम्भावना भी प्रबल हो जाती है। इसलिए इस रोग के उन्मूलन के लिए सरकारी स्तर पर गम्भीर प्रयासों की अत्यन्त आवश्यकता बनती जा रही है ।

श्री अविनाश राय खन्ना।

इस बैठक के अगले ही दिन मैंने राज्यसभा याचिका समिति के समक्ष अपनी एक याचिका भी प्रस्तुत कर दी। जिसमें टी.बी. उन्मूलन के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय को कुछ ठोस योजनाएँ बनाने के लिए प्रार्थना की गई है। इस रोग के उन्मूलन के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय पर्याप्त बजट का प्रावधान करे और देश के सभी हिस्सों में इस रोग के प्रति जनता को सचेत करने और उपचार की सुविधाएँ उपलब्ध कराने के ठोस प्रयास प्रारम्भ किये जायें। टी.बी. रोग के विरुद्ध किसी भी उपचार आदि के लिए सांसदों और विधायकों के क्षेत्रीय विकास फण्ड से भी राशि खर्च करने की अनुमति दी जानी चाहिए।

अक्सर लोगों में यह मान्यता बन जाती है कि टी.बी. रोग का पूर्ण इलाज सम्भव नहीं जबकि यह केवल एक अन्धविश्वास है। चिकित्सा विज्ञान टी.बी. रोगी को पूरी तरह से स्वस्थ भविष्य देने में सक्षम है परन्तु अन्धविश्वासी लोग टी.बी. का पूरा इलाज नहीं कर पाते। सरकार को इस रोग के इलाज पर विशेष ध्यान इसलिए भी देना चाहिए क्योंकि इस रोग के कारण एक व्यक्ति ही नहीं अपितु पूरी पारिवारिक व्यवस्था खराब हो जाती है । टी.बी. रोगी का पारिवारिक और सामाजिक बहिष्कार किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। यदि सावधानियाँ बरती जायें तो टी.बी. रोगी को स्वस्थ करने के साथ–साथ इसके संक्रमण को फैलने से भी रोका जा सकता है।

टी.बी. रोग हमारे फेफड़ों में कुछ विशेष कीटाणुओं के संक्रमण के कारण होता है, अतः उन लोगों के लिए भी कुछ सावधानियाँ आवश्यक हैं जो आज तक टी.बी. रोग ग्रस्त नहीं हुए। नियमित प्राणायाम के द्वारा हम फेफड़ों के माध्यम से अपने शरीर में ऑक्सीजन की आपूर्ति में वृद्धि कर सकते हैं। प्रतिदिन न्यूनतम तीन लीटर जल के सेवन से भी ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाने में सहायता मिलती है तो दूसरी तरफ शरीर से मल निष्कासन का कार्य भी सुचारू रूप से चलता रहता है। वैसे आज के औद्योगिक युग में घर से बाहर निकलते समय मुंह और नाक को ढकना ही एक विशेष सावधानी होगी, विशेष रूप से जब हम प्रदूषित वातावरण में खुले वाहन पर निकल रहे हों।

avinkhannamp@gmail.com

परिवार नियोजन, प्रजनन एवं यौन स्वास्थ्य तथा बाल स्वास्थ्य, महिला सशक्तीकरण पर विशेष जोर देते हुए जनसंख्या एवं विकास संबंधी मुद्दों पर निर्वाचित प्रतिनिधियों के सम्मिलन संबंधी एक–दिवसीय संवेदीकरण कार्यशाला

अप्रैल 1, 2017, उदयपुर, राजस्थान

भारतीय संसदीय संस्थानः जनसंख्या एवं विकास तथा राजस्थान सरकार द्वारा परिवार नियोजन, प्रजनन एवं यौन स्वास्थ्य तथा बाल स्वास्थ्य, महिला सशक्तीकरण पर विशेष जोर देने के उद्देश्य से पंचायती राज संस्थानों के लिए एक दिवसीय संवेदीकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया।

इस कार्यशाला का उद्घाटन श्री अर्जुन लाल मीणा, सांसद, उदयपुर, राजस्थान द्वारा किया गया। जिला परिषद, ब्लॉक समिति, ग्राम पंचायत एवं स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं सहित 225 से अधिक पंचायती राज संस्थानों के सदस्यों ने इस बैठक में भाग लिया।

श्री मनमोहन शर्मा, कार्यकारी सचिव, भारतीय संसदीय संस्थानः जनसंख्या एवं विकास द्वारा मुख्य अतिथि, अन्य गणमान्य व्यक्तियों तथा प्रतिभागियों का स्वागत किया गया। अपनी प्रारंभिक टिप्पणी में उन्होंने कहा कि इस कार्यशाला का उद्देश्य पंचायती राज संस्था सदस्यों के बीच आबादी एवं विकास के मुद्दों पर जागरूकता पैदा करना तथा उनके संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों की ओर ध्यान आकर्षित करना था।

डॉ. अभय कुमार, सदस्य, तकनीकी सलाहकार समिति, भारतीय संसदीय संस्थानः जनसंख्या एवं विकास तथा डॉ. संजीव टैंक, सी.एम.एच.ओ., उदयपुर, द्वारा कार्यशाला में दो अलग–अलग तकनीकी प्रस्तुतियां दी गयी। जहां डॉ. अभय कुमार ने उदयपुर जिले के विभिन्न जनसांखिकीय एवं प्रजनन व शिशु स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों को उठाया, वहीं डॉ. टैंक ने जिले की स्थिति में सुधार हेतु राज्य तथा केंद्र सरकार द्वारा उठाए गए विभिन्न कार्यक्रमों एवं पहलों के बारे में जानकारी दी।

श्री अर्जुन लाल मीणा, सांसद,, प्रतिभागियों को सम्बोधित करते हुए।

डॉ. कुमार ने कहा कि उदयपुर मुख्य रूप से एक आदिवासी जिला है। यह राष्ट्रीय औसत की तुलना में जनसांख्यिकी एवं प्रजनन तथा बाल स्वास्थ्य संबंधी लगभग सभी इष्टतम संकेतकों में पीछे

कार्यशाला में प्रतिभागी भाग लेते हुए।

है। सभी निर्वाचित प्रतिनिधियों को अपने संबंधित क्षेत्रों में इन मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए। डॉ. टैंक ने स्वास्थ्य केंद्रों पर उपलब्ध कई कार्यक्रमों एवं सेवाओं को उजागर किया तथा लोगों के स्वास्थ्य के लिए इन सेवाओं का लाभ उठाने के तरीके एवं साधन हेतु अपने सुझाव दिये।

माननीय अतिथि कार्यशाला में भाग लेते हुए।

अपने मुख्य भाषण में, मुख्य अतिथि, श्री अर्जुनलाल मीणा ने संवेदीकरण कार्यशाला के लिए उदयपुर जिले को चुनने के लिए भारतीय संसदीय संस्थानः जनसंख्या एवं विकास का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि एक आदिवासी जिला होने के नाते, उदयपुर, डॉ. अभय कुमार द्वारा उजागर कई संकेतकों की दृष्टि से काफी पीछे है। जिले के दूरदराज के क्षेत्रों में स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं का विस्तार करने की आवश्यकता है, जो पहाड़ी एवं आदिवासी प्रभुत्व वाले हैं। उन्होंने कहा कि इस दिशा में प्रयास किए जा रहें हैं एवं मुझे विश्वास है कि आंकड़ों के अगले दौर में निश्चित रूप से मातृ एवं शिशु देखभाल सेवाओं की विस्तृत श्रृंखला में जरूर सुधार दिखाई देगा।

मंच पर आसीन अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने भी कार्यशाला को संबोधित किया।

प्रस्तुतीकरण के बाद, सभी प्रतिभागियों को अपनी राय, मुद्दे, टिप्पणियां या प्रश्न व्यक्त करने के लिए कहा गया। कई प्रतिभागियों ने जिला स्तर पर ऐसे मुद्दों पर प्रकाश डालने के लिए भारतीय संसदीय संस्थानः जनसंख्या एवं विकास का आभार व्यक्त किया। उनका मानना था कि पंचायती राज संस्थानों के बीच व्यापक जागरूकता पैदा करने के लिए ऐसी कार्यशालाएं ब्लॉक एवं तहसील स्तर पर भी आयोजित की जानी चाहिए।

मुख्य अतिथि द्वारा सभी प्रतिभागियों को धन्यवाद देने एवं प्रमाणपत्र तथा स्मृति चिन्ह वितरण के साथ कार्यशाला का समापन हुआ।

कार्यशाला में प्रतिभागी भाग लेते हुए।

राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस पर मातृ स्वास्थ्य संबंधी गुणवत्ता, समानता एवं सम्मान हेतु राष्ट्रीय बैठक

अप्रैल 10, 2017, नई दिल्ली

माननीय श्री जे.पी. नड्डा, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, भारत सरकार प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए।

11 अप्रैल, 2017 को सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाने के लिए, भारतीय संसदीय संस्थानः जनसंख्या एवं विकास तथा व्हाईट रिबन गठबंधन द्वारा संयुक्त रूप से 10 अप्रैल, 2017 को इंडिया हैबिटेट सेंटर में सांसदों के साथ एक बैठक का आयोजन किया गया।

इस बैठक का उद्देश्य भारत में सुरक्षित मातृत्व के लिए व्हाइट रिबन गठबंधन द्वारा शुरू किए गए अभियान हमारा स्वास्थ्य, हमारी आवाज के तहत एक लाख महिलाओं की गुणवत्ता, समानता एवं सम्मान के लिए सामूहिक आवाज का हिस्सा था। अभियान के माध्यम से भारत में मातृ स्वास्थ्य देखभाल संबंधी गुणवत्ता की आवश्यकता एवं देश में प्रजनन तथा मातृ स्वास्थ्य में सुधार हेतु महिलाओं को प्रत्यक्ष रूप से शामिल करना था। बैठक में महिलाओं के बेहतर स्वास्थ्य पर ध्यान केन्द्रित करते हुए, वांछित गुणवत्तापूरक प्रजनन एवं मातृ देखभाल संबंधी विभिन्न मुद्दों तथा चुनौतियो पर प्रकाश डाला गया। महिलाओं के बेहतर स्वास्थ्य देखभाल संबंधी मुद्दों के लिए राजनीतिक नेतृत्व के साथ अपेक्षित परिणामों पर भी विचार किया गया। प्रतिभागियों ने भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए कई कार्यक्रमों जैसे जननी सुरक्षा योजना के माध्यम से मातृ स्वास्थ्य के मुद्दों पर चर्चा की।

इस बैठक को मुख्य अतिथि माननीय श्री जे.पी. नड्डा, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, भारत सरकार द्वारा संबोधित किया गया। डॉ. अपराजिता गोगोई, सुरक्षित मातृत्व हेतु राष्ट्रीय समन्वयक, श्री मनमोहन शर्मा, कार्यकारी सचिव, भारतीय संसदीय संस्थानः जनसंख्या एवं विकास द्वारा प्रतिभागियों का स्वागत किया गया। श्रीमती विप्लव ठाकुर, सांसद व उपाध्यक्ष, भारतीय संसदीय संस्थानः जनसंख्या एवं विकास द्वारा बैठक की अध्यक्षता की गई। बैठक में सांसदों एवं नागरिक समाज के सदस्यों सहित लगभग 200 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

इस अवसर पर, माननीय केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री द्वारा जारी 'प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य तथा यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य (2014–2016) पर विशेष जोर देते हुए जनसंख्या तथा स्वास्थ्य पर संसदीय प्रश्नों का विषयवस्तु विश्लेषण' नामक रिपोर्ट का विमोचन किया गया। यह विश्लेषण आई.ए.पी.पी.डी. द्वारा ए.एफ.पी.पी.डी. के अंशतः वित्तपोषण द्वारा किया गया था।

माननीय श्री जे.पी. नड्डा, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, भारत सरकार प्रकाशनों का विमोचन करते हुए।

टी.बी. रोग मुक्त भारत शिखर सम्मेलन एवं एक-दिवसीय मैत्रीपूर्ण भारत बनाम टी.बी. क्रिकेट टूर्नामेंट

अप्रैल 8, 2017, धर्मषाला, हिमाचल प्रदेष

टी.बी. रोग मुक्त भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन द यूनियन द्वारा टी.बी. रोगमुक्त भारत अभियान हेतु कार्यवाई के एक भाग के रूप में चैलेंज टी.बी. द्वारा समर्थित (यूएसएड के प्रमुख टी.बी. नियंत्रण कार्यक्रम; भारत में द यूनियन द्वारा लागू), द ग्लोबल फंड तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार तथा हिमाचल प्रदेश क्रिकेट संघ के सहयोग से किया गया।

टी.बी. रोग के खिलाफ लड़ाई में जागरूकता एवं गति बढ़ाने के लिए प्रमुख भारतीय हस्तियों सहित प्रमुख सरकारी अधिकारियों तथा सांसदों ने एक साथ सम्मेलन को संबोधित किया। सम्मेलन को संबोधित करते हुए, माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री जे.पी. नड्डा ने कहाः "सरकार 2025 तक टी.बी. समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। आज, संशोधित राष्ट्रीय टी.बी. नियंत्रण कार्यक्रम के तहत 10 मिलियन से अधिक टी.बी. रोगियों का इलाज किया गया है। परन्तु 2025 के लक्ष्य को पूरा करने के लिए हमें हमारे दृष्टिकोण में आक्रामकता लाने की आवश्यकता है एवं सोचने का एक नया तरीका अपनाना चाहिए। हमें टी.बी. का सामना सिरे से करना है, इसमें सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र, तथा इसी तरह के सम्मेलन हमें यह सब करने के लिए नए तरीके तलाशने का मौका देते हैं।"

इस कार्यक्रम ने टी.बी. रोग के मुद्दे पर राष्ट्रीय ध्यानाकर्षण किया है एवं भारत में टी.बी. रोग को समाप्त करने संबंधी संसाधनों के लिए सरकार, राजनेताओं, कॉरपोरेट भागीदारों तथा दाताओं सहित प्रमुख हितधारको से समर्थन तथा प्रतिबद्धता हासिल की है।

"टी.बी. मुक्त भारत संबंधी दृष्टि पर विचार करते हुए जीवन के सभी क्षेत्रों से एकजुट हितधारको को देखकर मुझे प्रसन्नता हो रही है... " – भारत के माननीय प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी ने अपने संदेश में कहा।

शिखर सम्मेलन में बोलते हुए, द यूनियन के कार्यकारी निदेशक जोस लुइस कास्त्रो ने कहा, "यदि हम भारत में टी.बी. रोग के कलंक का समाधान एवं इसके निदान में सुधार चाहते हैं, तो हमें रोग के बारे में जागरूकता एवं ज्ञान को बढ़ाने के लिए सभी हितधारकों को शामिल करने की आवश्यकता है।"

वक्ताओं तथा प्रतिभागियों में माननीय केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, भारत सरकार, श्री जे.पी. नड्डा; केन्द्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता राज्य मंत्री, श्री राजीव प्रताप रूढ़ी, तथा सांसद श्री अनुराग ठाकुर, श्री सैयद शहनवाज हुसैन, मोहम्मद अजहरूद्दीन (भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान) एवं अन्य शामिल थे। प्रमुख मशहूर हस्तियों की क्रिकेट टीम में श्री बॉबी देओल, श्री सोनू सूद, श्री सोहेल खान, श्री आफताब शिवदासानी, श्री सुनील शेट्टी एवं अन्य शामिल थे।

शिखर सम्मेलन में नागरिक समाज के प्रतिनिधियों, केन्द्रीय टी.बी. डिवीजन, केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, द यूनियन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, संयुक्त राज्य अमेरिका की अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी, भारतीय संसदीय संस्थानः जनसंख्या एवं विकास तथा द ग्लोबल फंड सहित सभी प्रतिभागी उपस्थित थे।

माननीय श्री जे.पी. नड्डा, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, भारत सरकार, खिलाडियों के साथ टी.बी. मुक्त भारत की शपथ लेते हुए।

भारतीय संसदीय संस्थानः जनसंख्या एवं विकास, द यूनियन तथा हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा संयुक्त रूप से टी.बी. पर पंचायती राज संस्थानो के लिए संवेदीकरण कार्यशाला

बारोट, जिला मंडी, हिमाचल प्रदेश, 10 जून, 2017

हिमाचल प्रदेश में टी.बी. के मुद्दे पर पंचायती राज संस्थानों के सदस्यों को परिचित करने एवं उनके संबंधित क्षेत्रों में टी.बी. रोग के उन्मूलन हेतु पंचायती राज संस्थानों के सदस्यों की भूमिका पर चर्चा करने के उद्देश्य से भारतीय संसदीय संस्थानः जनसंख्या एवं विकास, द यूनियन तथा हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा संयुक्त रूप से 10 जून, 2017 को बारोट, मंडी जिला, हिमाचल प्रदेश में टी.बी. रोग पर पंचायती राज संस्था सदस्यों के लिए एक संवेदीकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया।

श्री मनमोहन शर्मा द्वारा कार्यक्रम में उपस्थित सभी प्रतिभागियों का स्वागत किया गया। उन्होंने हिमाचल प्रदेश के माननीय स्वास्थ्य मंत्री, श्री कौल सिंह ठाकुर, विधान सभा सदस्य, श्री किशोरी लाल, श्री इंदरदेव जी, सचिव, जिला कांग्रेस समिति, जिला टी.बी. अधिकारी डॉ बरिया, विश्व स्वास्थ्य संगठन के परामर्शदाता डॉ रविंदर, द यूनियन विशेषज्ञ श्री शिवा श्रेष्ठ, श्री मनीष कुमार, एवं बारोट तथा बैजनाथ तहसील, मंडी जिला, हिमाचल प्रदेश के पंचायती राज संस्थानों के सदस्यों का अभिवादन किया।

डॉ. आर.के. बरिया, जिला टी.बी. अधिकारी ने मंडी जिले के चोहार घाटी/बारोट क्षेत्र में टी.बी. रोग के विशेष संदर्भ के साथ हिमाचल प्रदेश में टी.बी. की स्थिति के बारे में चर्चा की। उन्होंने टी.बी. रोग के लक्षण एवं संकेत के बारे में भी प्रकाश डाला, साथ ही टी.बी. नियंत्रण के लिए शीघ्र निदान तथा उपचार के महत्व पर भी जोर दिया।

डॉ. रविंदर ठाकुर, विश्व स्वास्थ्य संगठन सलाहकार, हिमाचल प्रदेश ने चोहार घाटी/बारोट क्षेत्र में टी.बी. रोग की समस्या एवं हिमाचल प्रदेश की समग्र स्थिति पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि 2015 में, राज्य में जहां 14000 टी.बी. रोगियों का पता चला, वहीं लगभग 530 टी.बी. रोगियों की मौत हुई। लगभग 500 टी.बी. रोगियों की उपचार के अभाव एवं उपचार में ढ़िलाई के कारण मौतें हुई। हर साल हम अकेले बारोट घाटी से 25–30 नए टी.बी. रोगियों की पहचान करते हैं।

माननीय स्वास्थ्य मंत्री हिमाचल प्रदेश, श्री कौल सिंह ठाकुर, अन्य अतिथियों के साथ कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए।

श्री मनीष कुमार, द यूनियन ने हिमाचल को टी.बी. रोग मुक्त राज्य बनाने में पंचायती राज संस्थानों के सदस्यों की भूमिका पर एक प्रस्तुति दी। उन्होंने कहा कि पंचायती राज संस्थानों के सदस्य अपनी ग्राम सभा बैठकों, स्वास्थ्य मेलों, विश्व टी.बी. दिवस, स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, पोषण दिवस आदि अवसरों पर टी.बी. रोग संबंधी मुद्दे पर चर्चा कर सकते है। पंचायती राज संस्थानों के सदस्यों को आगे आकर एवं एएनएम, आशा कार्यकर्ताओं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ टी.बी. के बारे में जागरूकता पैदा कर इस मुद्दे पर चर्चा करनी चाहिए तथा उन्हें टी.बी. रोग की रोकथाम एवं नियंत्रण के बारे में आम जनता तथा प्रभावित समुदाय के बीच संदेश प्रसारित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए।

हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य ठाकुर इंदरसिंह ने सभी पंचायती राज संस्थानों के सदस्यों से टी.बी. रोग की रोकथाम का संदेश, विशेष रूप से प्रभावित समुदाय के सभी आम लोगों के बीच प्रसारित करने की अपील की। ठाकुर इंदरसिंह ने टी.बी. रोगमुक्त हिमाचल प्रदेश के लिए समर्थन देने का संकल्प लिया एवं अपने निर्वाचन क्षेत्र में टी.बी. रोग पर आम जनता को जागरूक करने की दिशा में कार्य करने की रूचि व्यक्त की।

मंच पर आसीन गणमान्य अतिथि।

श्री प्रेम सिंह, प्रधान, ने बारोट घाटी में मंडी के पूरे जिले सहित टी.बी. रोग फैलने के खिलाफ कार्रवाई करने की तात्कालिकता पर प्रकाश डाला। उन्होंने कुष्ठरोग उन्मूलन, पोलियो उन्मूलन, लिंग अनुपात स्थिरीकरण, बेटी बचाओ, एवं मेरी लाडली कार्यक्रम पर

अभियान चलाने हेतु अपने पूर्वानुभव के साथ काम करने की इच्छा व्यक्त की। उन्होंने उल्लेख किया कि बारोट घाटी के लोगों को टी.बी. रोग के लक्षण एवं संकेतों की दिशा में शिक्षित किया जाना चाहिए। एक पंचायती राज संस्था सदस्य के रूप में आम जनता को जागरूक करने के प्रति उनका दायित्व है, विशेष रूप से टी.बी. रोग के संकेत व लक्षण के बारे में, ताकि टी.बी. रोग के प्रसार को प्राथमिक आधार पर नियंत्रित किया जा सके। उन्होंने जोर दिया कि लोग पूरी दवा की खुराक के महत्व एवं सरकारी सुविधा केंद्र में मुफ्त लागत तथा गुणवत्ता के उपचार के बारे में अनजान हैं।

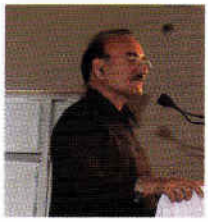

माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्री कौल सिंह ठाकुर प्रतिभागियों को सम्बोधित करते हुए।

अपने प्रमुख भाषण में हिमाचल प्रदेश के माननीय स्वास्थ्य मंत्री, श्री कौल सिंह ठाकुर ने विश्व में एवं भारत में टी.बी. रोग के कारण होने वाली मौतों पर प्रकाश डाला। भारत में टी.बी. रोग के कारण 4.5 लाख लोगों की मौत हुई। इसी तरह, हिमाचल में भी टी.बी. रोग से कई मौतें हुई। उन्होंने कहा कि यदि समय पर टी.बी. का इलाज नहीं होता है तो यह एम.डी.आर. मामले में परिवर्तित हो सकता है एवं एमडीआर रोगियों की जीवित रहने की दर केवल 50 प्रतिशत है। इसलिए, हमें इस रोग के संकेत, लक्षण, समय पर उपचार एवं अनुपालन के बारे में जानना आवश्यक है। सरकार टी.बी. रोग से लडने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है परंतु बिना पंचायती राज संस्थानों के सहयोग के, सरकार हिमाचल प्रदेश में टी.बी. मुक्त लक्ष्य को अकेले हासिल नहीं कर सकती है। टी.बी. रोग की प्रमुख चुनौतियों में जागरूकता, समय पर उपचार एवं अनुपालन का अभाव, पोषण की कमीं, धूम्रपान, पान मसाले का सेवन तथा अस्वास्थ्यकर जीवनयापन स्थितियां हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार ने सार्वजनिक स्थानों पर सिगरेट के उपयोग एवं एकल सिगरेट की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसी तरह, जनता के लिए पोषण, विशेष रूप से टी.बी. रोगियों के पोषण का ध्यान रखा जाना चाहिए।

यद्यपि हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य संकेतक भारत के अन्य राज्यों के मुकाबले बेहतर हैं, फिर भी हिमाचल प्रदेश के लोगों के स्वास्थ्य संकेतकों में बेहतर सुधार के लिए कई उपायों की जरूरत है। अगर राज्य के लोगों के समग्र स्वास्थ्य मानकों में सुधार होता है, तो टी. बी. रोग की घटनाओं में कमीं आने की संभावना रहती है। मैं पंचायती राज संस्थानों के सदस्यों से हिमाचल प्रदेश सरकार एवं उनके संबंधित पंचायतों के लोगों की सहायता करने तथा टी.बी. रोग की समस्या एवं समाधान के बारे में जागरूक बनाने की अपील करता हूँ। पंचायती राज संस्थान लोकतंत्र का चौथा स्तंभ हैं जो ग्राम सभा के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है। केन्द्र सरकार स्थानीय स्व–कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए सीधे पंचायतों को पैसे देती है, इसलिए प्रधान, पंचायत समिति सदस्यों, जिला परिषद सदस्यों को भी टी.बी. रोग संबंधी जागरूकता कार्यक्रम पर अपने धन का निवेश करने पर ध्यान क्रेंद्रित करना चाहिए।

सभा को संबोधित करते हुए, माननीय श्री किशोरी लाल, विधायक, बैजनाथ ने कहा, "टी.बी. रोग मुक्त भारत" भारत सरकार की बुद्धिमता है ठीक इसी तरह टी.बी. रोग मुक्त हिमाचल प्रदेश के लिए राज्य सरकार की बुद्धिमता होनी चाहिए एवं एक राजनेता के रूप में मैं टी.बी. रोग मुक्त हिमाचल के लिए प्रतिबद्ध हूँ। इससे पहले बारोट घाटी में गंडमाला (गले पर गांठ) काफी प्रचलित बीमारी थी लेकिन हमने इस बीमारी के खिलाफ़ लड़ाई लड़ी एवं अब हमारी यह घाटी गंडमाला–रोगमुक्त है। इसी तरह, हमें टी.बी. रोग से एक समर्पित समय–सीमा के भीतर निजात पानी है। हिमाचल प्रदेश सरकार सभी चिकित्सा अधिकारियों, पैरामेडिकल स्टाफ, आधुनिक नैदानिक सुविधाओं के साथ अवसंरचना स्थापित करके स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए कड़ी मेहनत कर रही हैं। यही नहीं, हमारे स्वास्थ्य मंत्री श्री कौल सिंह ठाकुर जी प्राथमिक स्वास्थ्य संबंधी सार्वजनिक स्वास्थ्य मुद्दों एवं चुनौतियों को संबोधित करने के प्रति बहुत सक्रिय हैं। मैं सभी जिला परिषदों, पंचायत समितियों, ग्राम पंचायतों एवं ग्राम सभाओं के सदस्यों से अनुरोध करता हूँ कि वे अपने संबंधित क्षेत्रों में टी.बी. रोग संबंधी मुद्दों पर अपनी बैठकों में चर्चा करें तथा इस रोग के संकेत, लक्षणों, रोकथाम, उपचार एवं इलाज के बारे में हर व्यक्ति को जागरूक बनाएं।

श्री मनमोहन शर्मा, कार्यकारी सचिव, भारतीय संसदीय संस्थानः जनसंख्या एवं विकास ने सभी गणमान्य व्यक्तियों एवं पंचायती राज संस्थानों के सदस्यों को इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए धन्यवाद दिया तथा सभी प्रतिभागियों को संगोष्ठी में सीखने का सर्वोत्तम उपयोग करने एवं हिमाचल प्रदेश को टी.बी.–मुक्त राज्य बनाने के लिए इसका सकारात्मक प्रयोग करने की अपील की।

कार्यशाला में पुरुषों सहित महिलाओं की भी उल्लेखनीय भागीदारी रही।

जनसंख्या एवं विकास पर एशिया तथा अरब सांसदों की बैठक एवं अध्ययन दौराः युवा वृद्धि से जनसांख्यिकीय लाभांश तकः क्षेत्रीय विकास एवं सतत् विकास लक्ष्यों की उपलब्धि की ओर

जुलाई 18–20, 2017, अम्मान, जॉर्डन

अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों, विश्लेषकों एवं संगठनों के अलावा, प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सांसदों, निर्वाचित जनप्रतिनिधियों द्वारा "जनसंख्या एवं विकास पर एशिया एवं अरब सांसदों की बैठक तथा अध्ययन दौरा; युवा वृद्धि से जनसांख्यिकीय लाभांश तकः क्षेत्रीय विकास तथा सतत् विकास लक्ष्यों की उपलब्धि की ओर" विषय पर जुलाई 18–20, 2017 को अम्मान, जॉर्डन बैठक में मुलाकात की गई।

यह बैठक एशियाई जनसंख्या एवं विकास संघ तथा जापानी जनसंख्या संसदीय संघ के सचिवालय द्वारा आयोजित की गई। इस बैठक की मेजबानी जॉर्डन सीनेट, अरब संसदीय संघः जनसंख्या एवं विकास द्वारा जापानी ट्रस्ट फंड; संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या निधि तथा अंतर्राष्ट्रीय नियोजित पितृत्व संघ के सहयोग से की गई।

श्री हुसैन दलवाई, सांसद, भारत एवं श्री मनमोहन शर्मा, कार्यकारी सचिव, भारतीय संसदीय संस्थानः जनसंख्या एवं विकास ने इस बैठक में भाग लिया।

बैठक में 2030 की कार्यसूची में जनसंख्या के परिप्रेक्ष्य में सांसदों का ध्यान केंद्रित किया गया, क्षेत्र में आधुनिक सामाजिक समावेश एवं जनसंख्या स्थायित्व संबंधी नीतियों तथा कार्यक्रमों के साथ ही उनके महत्वपूर्ण आदेश तथा कार्यों को जनसंख्या मुद्दों के नये लक्ष्यों में शामिल किया गया। बैठक में अच्छे अभ्यासों को साझा करने की

श्री हुसैन दलवाई, सांसद, भारत, (मध्य में) बैठक में भाग लेते हुए।

आवश्यकता पर चर्चा से पता चलता है कि आपातकालीन स्थितियों से निपटने का समय आ गया है एवं सांसदों को परस्पर ज्ञान बांटने के साथ ही समस्याओं से निपटने की जरूरत है। सांसदों का ज्ञान–साझाकरण उनके संबंधित देशों के साथ ही संबंधित क्षेत्रों की नीतियों की प्रभावशीलता को बढ़ा सकता है, विशेषज्ञों ने इस बात पर बल दिया।

बैठक में चर्चा की गई एवं आबादी तथा विकास में सुधार के लिए कानून बनाने एवं विकसित करने की दिशा में आने वाली बाधाओं के समाधान हेतु ठोस उपायों संबंधी मसौदा दस्तावेजों पर सहमति व्यक्त की गई।

बैठक के प्रतिभागियों का ग्रुप चित्र।

बहु–हितधारक मंचः

निरंतर विकास के लिए स्वस्थ एवं सक्रिय उम्र में निवेशः नवाचारी दीर्घकालिक देखभाल को बढ़ावा देने के लिए एक क्षेत्रीय दृष्टिकोण

अगस्त 15–17, 2017, हो ची मिन्ह सिटी, वियतनाम

एक बहु–हितधारक मंच – निरंतर विकास के लिए स्वस्थ एवं सक्रिय एजिंग में निवेशः नवाचारी दीर्घकालिक देखभाल को बढ़ावा देने के लिए एक क्षेत्रीय दृष्टिकोण विषय पर अगस्त 15–17, 2017, हो ची मिन्ह सिटी, वियतनाम में एपीईसी वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक तथा संबंधित बैठको का आयोजन किया गया। जापान सरकार, वियतनाम सरकार, एशियाई संसदीय मंचः जनंख्या एवं विकास, एशियान तथा पूर्वी एशिया हेतु आर्थिक अनुसंधान संस्थान, हेल्पेज इंटरनेशनल, जापानी अंतर्राष्ट्रीय विनिमय केंद्र तथा जापान के विदेश व्यापार संगठन द्वारा इसका सह–आयोजन किया गया।

(बांये से) श्री लक्ष्मी नारायण यादव, सांसद; श्रीमती विप्लव ठाकुर, सांसद; प्रो. पी.जे. कुरियन, उपाध्यक्ष, राज्य सभा तथा श्री मनमोहन शर्मा, कार्यकारी सचिव, भारतीय संसदीय संस्थानः जनसंख्या एवं विकास बैठक में भाग लेते हुए।

एशिया–प्रशांत क्षेत्र की 27 अर्थव्यवस्थाओं के लगभग 260 से अधिक प्रतिभागियों ने इसमें भाग लिया, जिसमें सांसद, सरकारी अधिकारी, शिक्षाविद, सेवा प्रदाता, पत्रकार, एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठनों तथा नागरिक समाज संगठनों के विशेषज्ञ शामिल थे। यह मंच क्षेत्र में तेजी से बढ़ती हुई वयोवृद्ध आबादी की चुनौतियों एवं अवसरों के जवाब में बुलाया गया था। 60 साल एवं इससे अधिक आयु वर्ग के व्यक्तियों की संख्या 2050 तक 1.3 बिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है – लगभग चार लोगों में से एक। इन जनसांखिकीय परिवर्तनों से उत्पन्न चुनौतियों के अनुकूल प्रभावी नीति की तत्काल आवश्यकता है। आज, एशिया–प्रशांत क्षेत्र दुनिया की आबादी का लगभग 40.5 प्रतिशत हिस्सा है, लेकिन यहां की बुजुर्ग आबादी, दुनिया के वरिष्ठ नागरिकों (65 वर्ष से अधिक आयु) के मुकाबले आधे से अधिक आबादी का प्रतिनिधित्व करती है एवं 2050 तक यह संख्या 70 प्रतिशत तक बढ़ जाएगी।

प्रो. पी.जे. कुरियन, उपाध्यक्ष, राज्य सभा एवं अध्यक्ष, भारतीय संसदीय संस्थानः जनसंख्या एवं विकास; श्री लक्ष्मी नारायण यादव, सांसद; श्रीमती विप्लव ठाकुर, सांसद; तथा श्री मनमोहन शर्मा, कार्यकारी सचिव, भारतीय संसदीय संस्थानः जनसंख्या एवं विकास ने इस बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया।

अपने महत्वपूर्ण संबोधन में, श्री केजो ताकेमी, सदस्य, हाउस ऑफ काउंस्लर्स, जापान; व अध्यक्ष, एशियाई संसदीय मंचः जनसंख्या एवं विकास ने कहा कि वृद्ध समाज न केवल आर्थिक चुनौती है बल्कि स्वास्थ्य तथा मानव सुरक्षा संबंधी मुद्दा भी है। इसका सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज की उपलब्धि पर एक महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा, जो संपूर्ण जीवनकाल में सभी के लिए सतत् विकास लक्ष्यों के तहत निर्धारित स्वस्थ एवं सक्रिय जीवन को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है, विशेष रूप से सतत् विकास लक्ष्य 3, जो सभी सरकारों से स्वस्थ जीवन सुनिश्चित करने तथा सभी आयु वर्गों के कल्याण को बढ़ावा देने की अपील करती है।

तेजी से बढ़ती उम्र की आबादी के निहितार्थों को संबोधित करने की तत्काल आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के साथ ही मंच के माध्यम से अपने अनुभव साझा करने, आबादी की बढ़ती उम्र के उपयोग तलाशने एवं क्षेत्र में आबादी की बढती उम्र की आगामी लहर की चुनौतियों पर चर्चा करने का उत्कृष्ट अवसर दिया गया। व्यापक विविधतापूर्ण अर्थव्यवस्थाओं एवं संस्कृतियों से आए प्रतिनिधियों ने एक साथ मिलकर उन संभावित तरीकों पर चर्चा की जो यह सुनिश्चित कर सकें कि सभी सहयोगात्मक रूप से काम कर सकें, ताकि इस दिशा में कोई पीछे न रहे।

प्रतिभागियों ने स्वीकार किया कि कुशल देखभालकर्ताओं की सहायता की गारंटी एक महत्वपूर्ण समस्या है जिसके लिए क्षेत्रीय दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। यह सहमति व्यक्त की गई कि इस क्षेत्र में अर्थव्यवस्थाओं के बीच व्यावसायिक प्रशिक्षण एवं आजीविका के विकास को प्रोत्साहित करने तथा सीमा–पार के आंदोलनों तथा देखभालकर्ताओं के संचलन की सुविधा हेतु सहयोग की आवश्यकता है।

श्री जॉस लुइस कास्त्रो, अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी निदेशक (पेरिस), द यूनियन के साथ बैठक

अप्रैल 11, 2017, नई दिल्ली

टी.बी. रोग एवं फेफड़े की बीमारी से लड़ने के लिए अप्रैल 11, 2017 को नई दिल्ली में सह–अध्यक्ष सांसदों, तथा भारत में टी.बी. नेटवर्क के सदस्यों द्वारा श्री जॉस लुइस कास्त्रो, अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी निदेशक, अंतर्राष्ट्रीय यूनियन के साथ एक बैठक का आयोजन किया गया। भारतीय टी.बी. रोग गठबंधन सांसदों का एक अनूठा नेटवर्क है जो भारत में टी.बी. रोग को समाप्त करने की दिशा में प्रतिबद्ध है। 'भारत में टी.बी. रोग नियंत्रण कार्यक्रम हेतु आगे की कार्रवाई – निर्वाचित प्रतिनिधियों का पक्षसमर्थन', पर चर्चा करने के उद्देश्य से भारतीय संसदीय संस्थानः जनसंख्या एवं विकास द्वारा 11 अप्रैल, 2017 को नई दिल्ली में यह बैठक आयोजित की गई थी।

माननीय सांसदों श्रीमती विप्लव ठाकुर, डॉ. माजिद मेमन, डॉ. किरीट सोलंकी, डा. बी.एन. गौड एवं श्री ए.बी. रपोलू बैठक में उपस्थित थे। इस बैठक में श्री जोस लुइस कास्त्रो, कार्यकारी निदेशक, द यूनियन, श्री प्रबोध भांबल, उप–कार्यकारी निदेशक, द यूनियन, डॉ. जेमी टॉसिंग, क्षेत्रीय निदेशक, द यूनियन दक्षिण–पूर्व एशिया कार्यालय, सुश्री कविता अय्यागरी तथा श्री शिवा श्रेष्ठ भी उपस्थित थे। डॉ. रूबेन स्वामिकन एवं डॉ. अमर शाह, यूएसएड भारत तथा श्री मनमोहन शर्मा, कार्याकारी सचिव, भारतीय संसदीय संस्थानः जनसंख्या एवं विकास ने भी बैठक में भाग लिया।

श्री जॉस लुइस कास्त्रो ने भारत में टी.बी. रोग संबंधी नेटवर्क की स्थापना एवं इस दिशा में महत्वपूर्ण पक्षसमर्थन के उद्देश्यों को परिभाषित करने के लिए सांसदों के प्रति आभार व्यक्त किया। बैठक के दौरान विभिन्न मुद्दों पर विचार–विमर्श किया गया, जिसमें राज्य/केंद्र सरकारों के साथ अनुबंध की स्थापना एवं नीतियों को सुधारने, बजट बढ़ाने, कार्यक्रमों को लागू करने आदि जैसे मुद्दे शामिल थे। द यूनियन तथा भारतीय संसदीय संस्थानः जनसंख्या एवं विकास ने भी भारत में टी.बी. रोग उन्मूलन के लिए दीर्घकालिक रणनीति की योजना बनाई।

केंद्र–राज्य प्रभावी साझेदारी शिखर सम्मेलन के माध्यम से टी.बी. रोग का उन्मूलन

28–29 जुलाई, 2017, नागपुर, महाराष्ट्र

भारतीय संसदीय संस्थानः जनसंख्या एवं विकास तथा टी.बी. व फेफड़ा रोग के विरूद्ध अंतर्राष्ट्रीय संघ द्वारा संयुक्त रूप से भारत मे तथा विशेषकर महाराष्ट्र में टी.बी. रोग की स्थिति को संवेदनशील बनाने एवं चर्चा करने के लिए विधायकों की एक बैठक का आयोजन किया गया। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तत्वाधान में श्री फग्गन सिंह कुलस्ते के नेतृत्व में 28–29 जुलाई, 2017 को नागपुर, महाराष्ट्र में यह आयोजन किया गया।

संसद के चार सदस्यों, श्री नानाभाउ फलगुनराव पाटोले, श्री कृपाल बालाजी तुमाने, श्री अशोक महादेवराव नेटे, डा. विकास महात्मे एवं दो विधान सभा सदस्यों, श्री सुधाकर विटठलराव कोहाले एवं डा. मिलिंद माने ने बैठक में भाग लिया।

सांसद एवं विधायक बैठक में भाग लेते हुए।

भारत में परिवार नियोजन एवं जनसंख्या स्थिरीकरणः चर्चा मंच

भारतीय संसदीय संस्थानः जनसंख्या एवं विकास, 7 जून, 2017

प्रो. पी.जे. कुरियन, उपाध्यक्ष, राज्य सभा, भारतीय संसदीय संस्थानः जनसंख्या एवं विकास के अध्यक्ष तथा एशियाई संसदीय मंचः जनसंख्या एवं विकास के उपाध्यक्ष द्वारा भारतीय संसदीय संस्थानः जनसंख्या तथा विकास की तकनीकी सलाहकार समिति के सदस्यों तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ बैठक की अध्यक्षता की गई। यह बैठक भारत में परिवार नियोजन एवं जनसंख्या स्थिरीकरण संबंधी मुद्दों पर चर्चा करने हेतु बुलाई गई थी।

जी 7 2017 शिखर सम्मेलन के लिए जनसंख्या एवं विकास पर सांसदों का वैश्विक सम्मेलन

4–6 मई, 2017, रोम (इटली)

जी 7 2017 शिखर सम्मेलन के लिए जनसंख्या एवं विकास पर सांसदों का एक वैश्विक सम्मेलन 4–6 मई, 2017 को रोम, इटली, में आयोजित किया गया।

सम्मेलन द्वारा उन अंतर्राष्ट्रीय संसदीय सम्मेलनों की परंपरा का पालन किया गया, जो जी 7/8 प्रेसीडेंसी वाले देशों के विकास एवं आबादी के विषय पर आयोजित किये गए थे

प्रो. पी.जे. कुरियन, उपाध्यक्ष, राज्य सभा, सम्मेलन में भाग लेते हुए।

प्रो. पी.जे. कुरियन, उपाध्यक्ष, राज्य सभा, व भारतीय संसदीय संस्थानः जनसंख्या एवं विकास के अध्यक्ष तथा एशियाई संसदीय मंचः जनसंख्या एवं विकास के उपाध्यक्ष तथा श्री मनमोहन शर्मा, कार्यकारी निदेशक, भारतीय संसदीय संस्थानः जनसंख्या एवं विकास ने सम्मेलन में भाग लिया।

सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य मानव अधिकार परिप्रेक्ष्य के माध्यम से प्रवसन पर था – विशेष रूप से महिलाओं के स्वास्थ्य संबंधी अधिकार एवं लिंग दृष्टिकोण। यह सहमति हुई कि बैठक में वैश्विक दक्षिण के मुद्दों पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया, जहां पर सबसे अधिक प्रवासी आबादी रहती है। यह सुझाव दिया गया कि भविष्य में उपलब्ध धन का उपयोग एशिया–प्रशांत क्षेत्र की गतिविधियों पर किया जाए।

इस सम्मेलन से पता चला है कि ईपीएफ क्षेत्र तथा एशियाई संसदीय मंचः जनसंख्या एवं विकास क्षेत्र की समस्यांए परस्पर काफी भिन्न हैं, यद्यपि मूल कारण समान हैं जैसे – आबादी तथा विकास संबंधी मुद्दे। इस सम्मेलन के दौरान एशियाई संसदीय मंचः जनसंख्या एवं विकास द्वारा प्राप्त दृश्यता भविष्य में उपयोगी साबित हो सकती है।

यह सम्मेलन रोम के सांसदों की अपील के साथ संपन्न हुआ, जिसे 45 देशों के प्रतिभागी सांसदों द्वारा अपनाया गया था। विभिन्न कार्रवाई बिंदुओं में, दुनिया के नेताओं से व्यापक लैंगिकता संबंधी शिक्षा प्रदान करने एवं संपूर्ण यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य सेवाओं संबंधी सार्वभौमिक पहुंच वाली स्वास्थ्य व्यवस्था स्थापित करने एवं उन नीतियों को अपनाना जो कि प्रवासियों के योगदान को गले लगाती हैं तथा सभी प्रवासियों, विशेष रूप से महिलाओं एवं बच्चों के मानव अधिकारों तथा मौलिक स्वतंत्रता संबंधी अधिकारों को संरक्षित करने वाली नीतियों को बढावा देना एवं उन्हें पूरा करना आदि शामिल थे।

नोबल पुरस्कार विजेता सुश्री आँग संन सु काइ, म्यांमार की विदेश मंत्री प्रतिभागियों को सम्बोधित करते हुए।

ए.एफ.पी.पी.डी. कार्यकारी सदस्यों का ग्रुप चित्र।

संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत डॉ. एरिक पी. गूज़बी के साथ भारत में टी.बी. रोग नेटवर्क संबंधी सह-अध्यक्षीय बैठक

11 अगस्तए 2017, नई दिल्ली

प्रतिभागियों का ग्रुप चित्र।

संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत डॉ. एरिक पी. गूज़बी के साथ भारत में टी.बी. रोग नेटवर्क संबंधी सह–अध्यक्षों की एक बैठक का आयोजन 11 अगस्त, 2017 को नई दिल्ली में किया गया। बैठक के दौरान, भारत में टी.बी. नेटवर्क के अध्यक्ष, प्रो. पी. जे. कुरियन, उपाध्यक्ष, राज्य सभा; सह–अध्यक्षों में श्रीमती विप्लव ठाकुर, सांसद, श्री माजिद मेमन, सांसद; डॉ. किरीट सोलंकी, सांसद; द यूनियन एवं भारतीय संसदीय संस्थानः जनसंख्या एवं विकास की तकनीकी सलाहकार समूह सदस्यों सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।

डॉ. एरिक पी. गूज़बी ने अपने परिचयात्मक भाषण में सांसदों को बैठक आयोजित करने के लिए धन्यवाद करते हुए कहा कि वे यहां सांसदों से मिलने एवं भारत में टी.बी. रोग की समस्या के बारे में चर्चा करने पर गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। मैं इस विषय पर गंभीर चर्चा के लिए तत्पर हूँ लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि आपके नेतृत्व में भारतीय लोग इसका समर्थन करने में सक्षम होंगे एवं पूरी दुनिया आपके द्वारा निर्धारित प्राथमिकताओं की सराहना करती है। आप न केवल अपने देश, बल्कि पूरी दुनिया के लिए अपना योगदान कर रहे हैं।

भारत में टी.बी. नेटवर्क के सह–अध्यक्ष एवं सांसद डॉ. किरीट सोलंकी, ने कहा कि हमारी पिछली तथा वर्तमान सरकारों द्वारा सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद, हम स्वीकार करते हैं कि हम टी.बी. रोग के प्रसार का सफलतापूर्वक उन्मूलन या इसे नियंत्रित करने में सक्षम नहीं है। वर्तमान सरकार द्वारा माननीय प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी तथा माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री जे.पी. नड्डा के नेतृत्व में एक नई राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति विकसित की है तथा इस नीति में टी.बी. रोग पर अधिक ध्यान केंद्रित है।

भारत में टी.बी. रोग नेटवर्क के सह–अध्यक्ष एवं सांसद, डॉ. माजिद मेमन ने कहा कि टी.बी. रोग से लड़ने के हमारे प्रयासों के दो पहलू हैं। सबसे पहले, टी.बी. रोग पीड़ितों के लिए दवाओं एवं उपचार का प्रावधान, ताकि इस रोग से होने वाली मौतों को रोका जा सके। दूसरा, टी.बी. रोग को उचित शिक्षा से रोका जा सकता है; इसमें आम लोगों को क्या करना है और क्या नहीं जैसे पहलुओं को शामिल किया जाना चाहिए। हम टी.बी. नेटवर्क के सदस्य के रूप में देश में इस रोग के प्रति जागरूकता सुनिश्चित कर सकते हैं जिससे लोग इस मुद्दे को समझ सकें एवं खुद को भी टी.बी. रोग से बचा सकें।

डॉ. आनंद भास्कर रपोलू, सांसद एवं टी.बी. नेटवर्क के सदस्य ने कहा कि इससे पहले कि हम टी.बी. रोग उन्मूलन की बात करें, हमें बात करनी होगी कि टी.बी. रोग से कोई मौत न हो एवं कोई टी.बी. रोगग्रस्त न हो। उन्होंने कहा, "मैं इस समय इस रोग के रोकथाम के बारे में चिंतित नहीं हूँ, लेकिन मैं एम.डी.आर–टी.बी. के बारे में अधिक चिंतित हूँ। हमारे कार्यक्रम में, सार्वजनिक एवं निजी दोनों क्षेत्रो में निःशुल्क एवं गुणवत्ता वाली दवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करने की आवश्यकता है, तभी इस रोग प्रभावित लोगों का कल्याण होगा।"

श्री लक्ष्मी नारायण यादव, सांसद एवं टी.बी. रोग नेटवर्क के सदस्य ने कहा, "सरकार टी.बी. रोग नियंत्रण की दिशा में काम कर रही है, परंतु निश्चित रूप से कुछ गैर–सरकारी संगठनों को भी इस दिशा में आगे आने की जरूरत है। मुझे 25 वर्ष की आयु में टी.बी. की बीमारी हुई थी, उन दिनों मे हमने एमडीआर–टीबी के बारे में कभी नहीं सुना था। हमारे पास स्ट्रेप्टोमाइसिन जैसी आम दवाईयां थी। समुदाय की वास्तविक समस्या टी.बी. रोग के बारे में ज्ञान, उपचार, जागरूकता की कमीं है, जिसे गैर–सरकारी संगठनों के माध्यम से फैलाया जा सकता है।"

डॉ. नदीमुल हक, सांसद एवं टी.बी. रोग नेटवर्क के सदस्य ने कहा, "मैं सहमत हूं कि टी.बी. रोग से लड़ने के लिए राजनीतिक इच्छा को बनाए रखने के लिए गति आवश्यक है। श्री रपोलू, सांसद एवं मैं लगातार ऐसा कर रहे हैं। मास्को की बैठक तथा संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत को एक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। हमारे राज्य पश्चिम बंगाल, विशेष रूप से मुख्य खनन क्षेत्र, टी.बी. रोग से प्रभावित है एवं अगर हम वास्तव में टीकों का विकास कर सकें तो यह इस दिशा में मददगार साबित होगा।"

जनसंदेश

संपादक

मनमोहन शर्मा

जनसंदेश एक त्रैमासिक पत्रिका है

भारतीय संसदीय संस्थान – जनसंख्या एवं विकास

(संयुक्त राष्ट्र के साथ विशेष परामर्शदाता स्थिति)

1/6, सीरा इन्स्टीट्यूशनल एरिया, खेल गॉव मार्ग, नई दिल्ली–110049

दूरभाषः 011–4165661/67/68/76, फैक्सः 011–41656660

ई.मेल: iappd@airtelmail.in, वेब साईट: www.iappd.org

Asha Enterprises: 9811854631